Projects of Maharashtra Pending Clearance

4398. SHRI NARESH C. PUGLIA: Will the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) the names of major and minor projects of Maharashtra pending clearance with Government; since how long these are pending;

(b) whether Government of Maharashtra have asked for financial assistance to the World Bank for completion of these projects ; and

(c) if so, what are the details in this regard ?

THE MINISTER OF PLANNING AND THE MINISTER OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI MADHAVSINH SOLANKI) : (a) As Statement is enclosed. (*See* below).

(b) and (c) The projects are posed to the World Bank by the Government of India and not by the individual State Government. Aproject is formally posed for consideration for inclusion in the effective pipeline of projects after all the clearances have been received.

Statement

Projects of Maharashtra State cleared by the concerned Central Ministries/ Departments from all engles and pending clearance in Planning Commission.

Sl. No.	Name of the Project	Date of recommendation by the Advisory Committee of Planning Commission for investment approval by Planning Commission
1.	Gosikhurd Irrigation Project	12-4-1988
2.	North Mand	16-10-1986
3.	Maharashtra Water Supply and Sewarage Project, Phase II	The project was examined in the Planning Commission from funding angle. Clarification on a few budgetary aspects are awaited from the State Government.

विदेशों में कार्य करने वाले भारतीय मजदूरों के साथ धोखाधड़ी किये जाने के संबंध में जांच

4399. **श्री राम नरेश यादव :** क्या क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों और भूतपूर्व सांसदों ने 3 जनवरी, 1988 को लिखे एक पत्र के द्वारा विदेशों में कार्यरत निर्माण कम्पनियों द्वारा, उनमें कार्य कर रहे भारतीय मजदूरों के साथ धोखाधड़ी किये जाने के संबंध में जांच कराये जाने की मांग की थी ;

(ख) यदि हां, तो यह जांच किस एजेंसी ने की थी और उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) जांच के बाद जिन कम्पनियों और व्यक्तियों को दोषी पाया गया है उनके नाम तथा पते क्या-क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्युरो (सी०बी०आई०) द्वारा जांच कराने का विचार रखती है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) किसी भी संसद सदस्य अथवा भूतपूर्व संसद सदस्य से 3-1-88 का कोई पत्र नहीं मिला । तथापि, प्रधान मंत्री को सम्बोधित भूतपूर्व संसद सदस्य श्री हुकम देव नारायण यादव का 7-1-88 का पत्र मिला । इस पत्र में यह शिकायत की गई थी कि निर्माण कम्पनियां उत्प्रवासियों से रुपया ले रही हैं तथा उनके खिलाफ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच कार्रवाई की जाय । श्रम मंत्रालय (संबंधित प्रशासी मंत्रालय) ने श्री यादव को यह सूचित किया कि विदेशों में कार्यरत अधिकांश निर्माण कम्पनियां सरकारी उपक्रम हैं तथा विदेशों में उनकी परियोजनाओं में तैनात कामगार आमतौर पर उनके अपने ही कर्मचारी होते हैं । गैर-सरकारी क्षेत्र की निर्माण कम्पनियां भी विदेशों में परियोजनायें चला रही हैं । उन्हें उत्प्रवासियों का शोषण रोकने संबंधी निवारक उपायों की भी सूचना दी गई थी । चूंकि श्री यादव ने कोई विशिष्ट विवरण नहीं दिये थे, अतः कोई जांच नहीं की गई ।

कृत्रिम पैट्रोल का उत्पादन

@1400. **श्री अजीत जोगी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कुछ व्यक्ति कृत्रिम पेट्रोल का उत्पादन करने की तकनीक जानते हैं ;

(ख) क्या सरकार इस तकनीक के उपयोग को बहुत पैमाने पर करने का विचार करेगी ताकि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी की पूर्ति की जा सके और इन पदों के आयात में कमी की जा सके ; और

(ग) क्या सरकार को केरल के एक गांव में एक व्यक्ति द्वारा कृत्रिम पेट्रोल उत्पादन करने की खोजी गई इस उत्पादन विधि की जानकारी है और यदि हां, तो क्या इस विधि को उपयोगी पाया गया है?

@Previously Unstarred Quetsion 3635 transferred from the 29th August, 1988.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन्) : (क) से (ग) हाल ही में केरल के एक युवक ने संश्लेषित पेट्रोल उत्पादन में सफलता प्राप्त करने का दावा किया है । सी०एस० आई०आर० के वैज्ञानिकों से इस दावे का सत्यापन और उत्पाद की जांच करने के लिये कहा गया है ।

Conviction of Government Employees on Corruption Charges

4401. SHRI [illegible] CHIMANBHAI MEHTA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether there is any proposal of Government to disclose the names of the convicted officials involved in corruption charges ;

(b) if so, the reasons thereof;

(c) state the number of convicted during the last three yers from Government and Semi-Government Organisations for corruption charges and

(d) whether corruption is increasing in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM) : (a) and (b) It is the practice of Government to highlight convictions secured in anti-corruption cases through statements to the Press.

(c) and (d)

Year	No. of officials convicted
1986	152
1987	158
1988 . . . . . (upto 31-7-88)	89